पंचदश

बिहार विधान-सभा

तृतीय सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि — 27 आषाढ़, 1933 (श०) / 18 जुलाई, 2011 (ई०)

प्रश्नो की कुल संख्या—38

(1)	गृह विभाग	.. ..	18
(2)	कारा विभाग	.. ..	02
(3)	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	.. ..	04
(4)	उद्योग विभाग	.. ..	03
(5)	वित्त विभाग	.. ..	03
(6)	वाणिज्य-कर विभाग	.. ..	01
(7)	गन्ना उद्योग विभाग	.. ..	02
(8)	सांख्यिक वित्त विभाग	.. ..	02
(9)	सूचना प्रावैधिकी विभाग	.. ..	01
(10)	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (नागरिक विमानन)	..	02
	कुल योग	..	38

विद्यालय खोलना

*1. श्री रमेश ऋषिदेव--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला में अल्पसंख्यक के लिये आवासीय विद्यालय नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि अल्पसंख्यक के आवासीय विद्यालय नहीं रहने के कारण उक्त जिला के अल्पसंख्यक के पठन-पाठन में कठिनाई होती है;

(3)यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जिला में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोलने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

थाना का दर्जा देना

*2. श्री अब्दुल गफूर--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला अन्तर्गत जलई ओ०पी० की स्थापना वर्ष 1972 में की किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि जलई ओ०पी० जो थाना बनने की सभी शर्तों को पूरा करता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जलई ओ०पी० को थाना का दर्जा देने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मुक्त करना

*3. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 27 अगस्त, 2008 को प्रकाशित शीर्षक ''राजधानी को ठिकाना बना रहे माओवादी'' को ध्यान में रखते हुए,क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के पोस्टल पार्क,अगमकुआं व बेठर इलाका में भाकपा माओवादी का ठहरने और गतिविधि का मुख्य केन्द्र बना हुआ है;

(2) क्या यह बात सही है कि पुलिस की कार्रवाई के समय महिला माओवादी बसन्ती देवी और हार्डकोर उग्रवादी मनोज कुमार पुलिस की नजर बचाकर निकल गए हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार माओवादी द्वारा पटना को ठिकाने बनाने से मुक्त करने का कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अधिग्रहण करना

*4. श्री विजय कुमार सिन्हा--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिला-वर्गत औद्योगिक क्षेत्र का रकबा वर्ष 1994 से 8 एकड़ जमीन में 25 लघु एवं कुटीर उद्योग चल रहे हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि विगत 5 वर्षों से सरकार द्वारा 150 कुटीर उद्योग एवं लघु की स्वीकृत है लखीसराय जिला में औद्योगिक क्षेत्र का जमीन नहीं होने के कारण उक्त उद्योगों की स्थापना करने में कठिनाई हो रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उद्योग लगाने हेतु जमीन अधिग्रहण करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मकान का निर्माण

*5. श्रीमती गुलजार देवी--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत भेजा थाना को अपना भूमि एवं भवन नहीं रहने के कारण प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में काफी कठिनाई हो रही है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त थाना काफी संवेदनशील इलाके का थाना है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त थाना को जमीन एवं मकान निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पेंशन देना

*6. श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सन् 1974 के जे०पी० आन्दोलन में शामिल लोगों को सरकारी घोषणा के अनुरूप खगड़िया जिला एवं बांका जिला में चयनित व्यक्तियों को अबतक पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सभी चयनित व्यक्तियों को पेंशन देने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

लागू करना

*7. श्रीमती रेणु देवी-- दिनांक 17 जून, 2011 को स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित " ट्रैक्टर अनुदान के लिए बैंक से लोन की बाध्यता खत्म" शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, सांख्यिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि ट्रैक्टर खरीद पर अनुदान लेने की व्यवस्था केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही लागू है;

(2) क्या यह बात सही है कि इस व्यवस्था को निजी फाईनेंस कंपनियों एवं अन्य स्रोतों से लोन देने वाले एजेंसियों में भी लागू करने की घोषणा की गयी है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इस व्यवस्था को कबतक लागू करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

जाँच कराना

*8. श्री शशि भूषण हजारी--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा प्रक्षेत्र पुलिस बल में पदस्थापित अवर निरीक्षक मो० सनउल्लाह अवैध रूप से अर्जित राशि से चम्पारण जिले के नरकटियागंज शहर के डाक्टर कॉलोनी में दस लाख रुपये से अधिक राशि से आलीशान मकान बनाये हैं, तथा एक करोड़ की राशि से कीमती भू-खंड पत्नी के नाम से खरीद की है;

(2) क्या यह बात सही है कि बेतिया जिला शिकारपुर थाना क्षेत्र के रसटी गांव निवासी अवर निरीक्षक मो० सनउल्लाह ने अवैध धनोपार्जन कर अपने पुत्र तथा पुत्री को किशनगंज तथा अलीगढ़ स्थित मेडिकल कॉलेज एवं इंजिनियरिंग कॉलेज में बीस-बीस लाख रुपये डोनेशन देकर दाखिला कराया और फीस के नाम पर लाखों रुपया सलाना भुगतान किया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने वाले उक्त पुलिस पदाधिकारी के अवैध सम्पत्ति की जाँच निगरानी विभाग से कराने की विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ऋण देना

*9. श्री दुलालचन्द्र गोस्वामी--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 15 सूत्री अल्पसंख्यक कल्याण समिति के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को स्वरोजगार हेतु ऋण देने का प्रावधान है;

(2) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बलरामपुर प्रखंड एवं बारसोई प्रखंड किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को स्वरोजगार हेतु वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में ऋण नहीं दिया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त प्रखंडों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को स्वरोजगार हेतु कबतक ऋण देने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

पेंशन देना

*10. श्री राम प्रवेश राय--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार जे०पी० आन्दोलन और आपातकाल के समय सन् 1974 से 1977 तक मीसा और डी०आई०आर० में जेल में बन्द रहने वाले आन्दोलनकारियों को जे०पी० सम्मान योजना अन्तर्गत सम्मान स्वरूप पेंशन राशि देने का कार्यक्रम चला रही है;

(2) क्या यह बात सही है कि जे०पी० आन्दोलन और आपातकाल के समय गोपालगंज, सीवान और सारण जिला में दो सौ से अधिक आन्दोलनकारी मीसा और डी०आई०आर० में बन्दी बनाये गये थे, जो आवेदन देने के बावजूद अभीतक उक्त सम्मान पेंशन राशि से वंचित है;

(3) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज, सीवान और सारण जिलों में जे०पी० आन्दोलन और आपातकाल के समय मीसा, डी०आई०आर० में जेल में गये बंदियों की सूची संबंधित जेलों में नहीं रहने के कारण सैकड़ों लोग सम्मान योजना से अभीतक वंचित हैं;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जे०पी० सम्मान योजना से वंचित गोपालगंज, सीवान और सारण जिले के आन्दोलनकारियों को निर्धारित मापदंड के अनुसार पेंशन देने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चयन करना

*11. श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जिला पुलिस बल एवं बिहार सशस्त्र बल के जवानों की बहाली सिपाही चयन आयोग द्वारा की जाती है;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार सशस्त्र बल में समूह ''ग'' अन्तर्गत ट्रेड रैंक पुलिस एवं समूह ''घ'' अन्तर्गत अनुचर की बहाली कमान्डेन्ट द्वारा की जाती है;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों तरह के पुलिस बल का वेतनमान आदि समान है जबकि बहाली की प्रक्रिया अलग-अलग रखा गया है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार समूह ''ग'' एवं ''घ'' के पदों पर चयन सिपाही चयन आयोग द्वारा कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जाँच कराना

*12. श्री राम बालक सिंह--दिनांक 22 दिसम्बर, 2010 को हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित शीर्षक ''लूट-खसोट का खेल'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि थाने पर जगह की कमी, रास्ते की अनुपलब्धता एवं अन्य कारणों से कुर्की-जब्ती में जब्त सामानों को जिम्मेनामा के तहत किसी पदाधिकारी या उस इलाके के संभ्रांत व्यक्ति के पास कुछ दिनों तक रखने का प्रावधान है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न मामलों में कुर्की-जब्ती या अन्य कार्रवाई में पुलिस द्वारा जब्त सामानों का कोई अता-पता नहीं है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूरे राज्य में जिम्मेनामा के तहत रखे गए सामानों की भौतिक स्थिति की जाँच कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चालू करना

*13. श्री राजेश्वर राज--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के बिक्रमगंज अनुमंडल में वर्ष 2001 से ही उप-कोषागार भवन निर्मित है, परन्तु उप-कोषागार अभीतक चालू नहीं किया गया है, यदि हां, तो सरकार बिक्रमगंज में उप-कोषागार चालू करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सुनिश्चित करना

*14. डा० इजहार अहमद--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में वर्ष 2007 में 4000 आग लगी, वर्ष 2008 में 4210 की आग लगी वर्ष 2009 में 4000 आग लगी एवं वर्ष 2010 में 5000 आग लगी की घटनाएं हो चुकी है;

(2) क्या यह बात सही है कि इस वर्ष अप्रील माह तक कुल 105 दिनों में 107 आग लगी की घटना घट चुकी है लेकिन आग लगी के बचाव हेतु दमकल भी सही रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं जिससे राज्य के राजस्व की काफी हानि हो रही है;

(3) क्या यह बात सही है कि पटना स्थित 15 लाख लोगों को बचाने हेतु कम-से-कम 12 हाईड्रेट की आवश्यकता के विरूद्ध 4 हाईड्रेट ही कार्यरत हैं;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में आग लगी में सुरक्षा प्रदान करने हेतु 8 हाईड्रेट की कमी को कबतक सुनिश्चित करने का विचार रखती है और नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*15. श्री राम प्रवेश राय--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत मांझागढ़ थाना को कार्यालय तथा पुलिस पदाधिकारियों और आरक्षियों को रहने हेतु भवन उपलब्ध नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि कार्यालय तथा आवास व्यवस्था के अभाव में थाना-स्टाफ को काम करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मांझागढ़ थाना में कार्यालय एवं थाना-स्टाफ के आवास हेतु भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

थाना स्थापित करना

*16. श्री अवनीश कुमार सिंह--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत उग्रवाद प्रभावित पताही प्रखंड के सुगापीपर ग्राम में थाना नहीं रहने के कारण यहां की जनता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हां, तो क्या सरकार सुगापीपर ग्राम की जनता को सुरक्षा देने हेतु सुगापीपर में थाना स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन बनाना

*17. श्री विनय कुमार सिंह--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत थाना अवतारनगर चीनी मिल के भवन में चल रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि अवतारनगर थाना को अपना भवन नहीं है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अवतारनगर थाना का भवन बनाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

तालीमी मरकज खोलना

*18. श्री नौशाद आलम--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि साक्षरता में पिछड़े बिहार के सभी अल्पसंख्यक बहुल जिला में तालीमी मरकज खोलने का प्रावधान है;

(2) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के ठाकुरगंज एवं दिघल बैंक प्रखण्डों में एक भी तालीमी मरकज नहीं खुला है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (2) में वर्णित प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों में तालीमी मरकज खोलने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्थापित करना

*19. श्री जनक सिंह--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत पानापुर एवं तरैया प्रखंडों के दियारा क्षेत्र उग्रवाद से प्रभावित है, तो क्या सरकार पानापुर प्रखंड के कोंध भगवानपुर में पुलिस चौकी स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ओ० पी० बनाना

*20. श्रीमती (प्रो०) उषा सिन्हा--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के हिलसा अनुमंडल के योगीपुर कोरमा, चिकिसौरा तथा भिर्जापुर आदि पंचायतों के सुदूरवर्ती गांव हिलसा थाना के अन्तर्गत आता है, जिसकी दूरी हिलसा से 12 से 16 कि०मी० तक है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त थाना से दूर रहने के कारण इस अति पिछड़े इलाके में आम जनता की सुरक्षा में कठिनाई होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार योगीपुर ग्राम में ओ० पी० बनाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सुरक्षित रखना

*21. डॉ० फैयाज अहमद--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय (नागरिक विमानन्) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी स्थित हवाई अड्डा की घेराबन्दी का कार्य वर्ष 2009-10 में ही शुरू हुआ था लेकिन अभीतक उसके बाउंड्री वॉल एवं गेट का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है;

(2) क्या यह बात सही है कि बाउंड्री वॉल एवं गेट का निर्माण नहीं होने से हवाई पट्टी का उपयोग वाहन चलाना सीखने एवं आम रास्ता के रूप में किया जा रहा है, जिससे हवाई पट्टी काफी क्षतिग्रस्त हो गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मधुबनी स्थित हवाई अड्डा के बाउंड्री एवं उसके गेट का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर हवाई पट्टी को सुरक्षित करने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार कराना

*22. मो० आफाक आलम--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियां जिला के कसबा प्रखंड के बरैटा पंचायत में कलानन्द उच्च विद्यालय, कढ़वनैली का अल्पसंख्यक छात्रावास विगत 5 वर्षों से जर्जर अवस्था में है, यदि हां, तो उक्त छात्रावास का जीर्णोद्धार करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*23. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह-- क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के सरकारी विभागों द्वारा विगत 5 वर्षों में विकास एवं सामाजिक कार्यों में खर्च होनेवाली राशि को खर्च न कर राजकोष से 407 करोड़ की राशि की निकासी, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 328.36 करोड़, कल्याण विभाग द्वारा 12.66 करोड़, जल संसाधन विभाग द्वारा 12.65 करोड़, मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा 11.05 करोड़, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 6.73 करोड़, उद्योग विभाग द्वारा 5.67 करोड़, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 5.26 करोड़ एवं पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा 5.18 करोड़, यानी कुल 507 करोड़ की राशि की निकासी उक्त वर्णित अवधि में की गई है, परन्तु सामाजिक कार्यों में राशि खर्च नहीं की गई है, यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है तथा इसकी उच्चस्तरीय जाँच कर संबंधित पदाधिकारियों पर कबतक कार्रवाई करने का विचार सरकार रखती है, और नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*24. श्री विनोद नारायण झा--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार शीर्षक "12 बजे लेट नहीं 3 बजे भेंट नहीं" के आलोक में क्या मंत्री, गृह कारा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना स्थित आदर्श केन्द्रीय कारा बेउर सहित राज्य के अन्य कारागों में विगत् 5 वर्षों में 100 से अधिक कैदियों की मौत वहां पदस्थापित डॉक्टरों के लापरवाही के कारण हुई है, यदि हां, तो क्या सरकार जेल में बन्द कैदियों की हो रही असामयिक मृत्यु के लिए जवाबदेह लापरवाह डाक्टरों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्थापित करना

*25. श्री विनय कुमार सिंह--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला के दिघवारा प्रखण्डान्तर्गत सीतलपुर में भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा इन्डलैंड कन्टेनर डीपो (आई० सी० डी०) की स्थापना की स्वीकृति 2 अप्रील, 2002 में दिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि इन्डलैंड कन्टेनर डीपो को स्थापित करने हेतु सरकार को जमीन उपलब्ध कराना था, जो अबतक नहीं कराया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जमीन उपलब्ध कराकर कन्टेनर डीपो की स्थापना कराने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*26. श्री सदानन्द सिंह--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र दिनांक 28 जून, 2011 में प्रकाशित समाचार शीर्षक "तीन महीने में खर्च हुआ योजना बजट का तीन प्रतिशत" के आलोक में क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि योजना मद की शेष राशि को व्यय करने हेतु सरकार कौन-कौन-सी कार्रवाई करने जा रही है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चालू करना

*27. श्री रामदेव महतो--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला में अवस्थित रैयाम चीनी मिल का लीज स्वीकृत हो गया है, तिरहुत इन्टरनेशनल लि०, दिल्ली के साथ एकरारनामा दो साल पहले हो गया है, यदि हां, तो सरकार उक्त मिल को कबतक चालू कराने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

फाड़ी की व्यवस्था

*28. श्री जितेन्द्र कुमार--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के बिन्द प्रखंड के जिराईन नदी का पश्चिमी इलाका नदी पर पुल एवं सड़क नहीं रहने की वजह से वर्षात एवं अन्य दिनों में आवागमन में काफी असुविधा होती है तथा पुलिस गस्ती नहीं हो पाती है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रशासन को चुस्त-दुरूस्त रखने एवं पुलिस की गस्ती को नियमित रखने हेतु उच्च विद्यालय अमरावती के निकट पुलिस फाड़ी की व्यवस्था करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

आंवटित करना

*29. श्री सदानन्द सिंह--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि उद्योग विभाग के विशाहा द्वारा भागलपुर जिले के कहलगांव प्रखंडान्तर्गत लघु एवं मध्यम उद्योग लगाने हेतु वर्ष 2007 में भूमि अर्जित की गयी थी;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार अबतक उद्योग विभाग के द्वारा उक्त अधिगृहित भूमि में किन-किन उद्योगों को कब-कब कितनी जमीन आवंटित की गई है ?

भुगतान करना

*30. श्री मंजीत कुमार सिंह--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रीगा चीनी मिल सीतामढ़ी के द्वारा वर्ष 2010-11 में गन्ना किसानों का 30 करोड़ रुपये का बकाया मूल्य का भुगतान नहीं कराया गया है, यदि हां, तो क्या सरकार गन्ना किसानों के बकाया मूल्य का भुगतान कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*31. श्री राम बालक सिंह--क्या मंत्री, सांख्यिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य 323 के जगह मात्र 22 आवेदनों को ही समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा स्वीकृत किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिले के 66 समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा में से मात्र 8 शाखा ने ही परियोजना का वित्त पोषण किया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो लक्ष्य के विरुद्ध इतना कम उपलब्धि हेतु दोषी शाखा प्रबंधकों को दंडित करने हेतु सरकार कबतक क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

निर्गत करना

*32. श्री विनोद नारायण झा--क्या मंत्री, वित्त (वाणिज्य-कर) विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने फरवरी, 2011 में वाणिज्य-कर विभाग में वैधानिक प्रपत्र ''एफ'' ''सी'' एवं ''डी-1×'' को ऑनलाईन निर्गत करने का निर्णय लिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पाँच महीना बीत जाने के बावजूद अभीतक उक्त प्रपत्र को ऑनलाईन निर्गत नहीं किया जा सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड 1 में वर्णित प्रपत्र को कबतक ऑनलाईन निर्गत करने का विचार रखती है ?

व्यवस्था चालू करना

*33. श्री जितेन्द्र कुमार--क्या मंत्री, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2010 में निर्णय लिया है कि राज्य के सभी प्रखंडों में बी०डी०ओ० कान्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की जायेगी ;

(2) क्या यह बात सही है कि नालान्दा जिलान्तर्गत अस्थांवा विधान-सभा क्षेत्रान्तर्गत सरमेरा, अस्थांवा, बिन्द एवं कतरी सराय प्रखंडों में आजतक बी०डी०ओ० कान्फ्रेंसिंग की व्यवस्था नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सरकारी नियमानुसार आजतक उक्त वर्णित प्रखंडों में बी०डी०ओ० कान्फ्रेंसिंग की व्यवस्था नहीं किये जाने का क्या औचित्य है तथा उक्त व्यवस्था तक उक्त प्रखंडों में चालू करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

सुधार करना

*34. श्रीमती रेणु देवी-- दिनांक 26 जून, 2011 को स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित ''कौन लेगा छोटे शहरों की हवाई पट्टियों की सुध'' शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय (नागरिक विमानन) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णियां में हवाई अड्डों के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इसके बावजूद भी इन जगहों की हवाई पट्टी जर्जर है, जिससे विमानों का उतरना संभव नहीं हो पाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन जगहों के हवाई पट्टियों का सुधार करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बहाल करना

*35. डॉ० अच्युतानन्द-- दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 10 अप्रील, 2011 के अंक में छपी खबर के आलोक में क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में हर साल अगलगी की तीन हजार से अधिक घटनाएँ घटती हैं, जिसमें करोड़ों की सम्पत्ति तो खाक होती है, कई जिंदगियाँ भी आग की भेंट चढ़ जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य अग्निशमन विभाग में 80 प्रतिशत पद रिक्त हैं और पिछले 19 वर्षों से कोई बहाली नहीं हुई है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अग्निशमन विभाग के रिक्त पदों पर बहाली करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन की मरम्मती

*36. श्री दुर्गा प्रसाद सिंह-- हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 20 जून, 2011 को प्रकाशित शीर्षक ''नदी थाना में दरार, सहमे पुलिसकर्मी'' की ओर ध्यान देते हुए क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के फतुहा में राज्य का पहला नदी थाना खोला गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त थाना के भवन एवं परिसर में दरार आ गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त थाना के भवन के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जाँच कराते हुए भवन मरम्मत करवाने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

स्थापित करना

*37. श्रीमती मुन्नी देवी--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत अंचल शाहपुर के थाना बिहियां अंतर्गत बेनवलिया बाजार में वर्ष 1982 से 2003 तक पुलिस चौकी स्थापित थी परंतु वर्ष 2003 के बाद से इसे हटा दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बाजार में भारतीय स्टेट बैंक की बृहत शाखा होने सहित बड़े पैमाने पर व्यवसाय होता है परंतु इस बाजार से बिहियां थाना की दूरी लगभग 15 किलो मीटर होने के कारण बैंक, बाजार सहित आस-पास के गाँवों में हत्या, चोरी एवं लूट जैसी आपराधिक घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार व्यवसायियों एवं आमजनों की सुरक्षा सहित आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने हेतु उक्त बाजार में पुनः पुलिस चौकी स्थापित करने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सुदृढ़ करना

*38. डॉ० इजहार अहमद-- स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र दिनांक 2 जून, 2011 को प्रकाशित शीर्षक ''जेलों में नहीं हुई 28 साल से बहाली'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, कारा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में 54 जेल, 6 केन्द्रीय, 33 मंडल एवं 15 उप-कारा में कुल स्वीकृत पद 5100 के बदले मात्र एक हजार सिपाही व हवलदार से 14 से 16 घंटे ड्यूटी लो जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जेलकर्मियों की कमी के कारण जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जेलों में स्वीकृत पदों पर शीघ्र बहाली कर जेल की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना:
दिनांक, 18 जुलाई, 2011 (ई०) ।

गिरीश झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

बि०स०मु० (एल०ए०), 22 डी०टी०पी०-450